निर्णायक समझौता: कश्मीर और अफ़गानिस्तान दोनों समस्याओं का हल

अमेरिका और भारत दोनो एक ही देश से पीड़ित है , पाकिस्तान | समस्या भी एक ही है, पाकिस्तानी सेना द्वारा चोरी छुपे जिहादियों का पोषण, संरक्षण, प्रोत्साहन, एवं सैन्य मदद | समस्या , हालांकि साझी है, दोनो की बेबसी से कारण अलग अलग हैं | भारत की सेनाएँ, इस काबिल तो हैं कि पाकिस्तान के जिहादी ठिकाने नष्ट कर सकें , वे संभावित युद्ध के परिणामों को नियंत्रित रखने में सक्षम नहीं है, शक्ति मे बढ़त इतनी नही है कि पाकिस्तानी सेना को स्तंभित किया जा सके | किसी भी सैन्य कारवाही से पहले, शक्ति असंतुलन इतना अधिक होना चाहिए कि पाकिस्तानी सेना लड़ने की सोचे ही नही, सीधे हथियार डाल दे | दूसरी और अमेरिकी और नाटो सेनाओं के पास ऐसी शकित है , कि यदि वे उसे पूरी तरह प्रयोग में लाएँ तो पाकिस्तानी सेना के पास कोई जवाब ही नही है , फिर भी अमेरिका कोरी धमकी देकर पाकिस्तानी सेना को समझाने बुझाने का प्रयत्न करने लगता है | कारण, वह जमीन पर अपने सैनिक नही खोना चाहता |

जमीन पर सेना भेजे बिना , नियंत्रण में दीर्घकालिक बदलाव नहीं लाया जा सकता | वायुसेना और जहाजों द्वारा आप तबाही तो मचा सकते हैं , नियंत्रण मे परिवर्तन नही ला सकते |
पिछले ५० वर्षो में लगभग सभी समाजों का ढांचा बुनियादी तौर पर बदल गया है | कुछ दशकों पहले तक हर परिवार में अमूमन ४-६ बच्चे होते थे | आज यह संख्या १ या २ हो गई है | जब ४ या ६ बच्चे होते थे तब युद्ध में यदि १ या २ शहीद भी हो गए तो समाज की संरचना पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता था | धटना परिवार को संतप्त करती थी , लेकिन परिवार निराशा के गर्त में जा कर बदहाली का शिकार नहीं हो जाता था | आज , यदि परिवार का अकेला जवान लड़का युद्ध में मारा जाये तो यह परिवार के लिए पूर्ण विनाश का संदेश होगा | उनको जीने का उदेश्य छिनता हुआ लगेगा | किसके लिए जिएँ, यह सवाल खड़ा हो जाएगा | पूरी समाज पर इसकी गहन प्रतिक्रिया होगी | इसीलिए अमेरिका आज ड्रोन अथवा वायुसेना द्वारा हमला करने में तो नहीं हिचकिचाता , सैनिक भेजने से पहले दस बार सोचता है |

मुस्लिम देश इसमे अपवाद हैं | वहाँ आज भी छोटे परिवारों का चलन नहीं है | मुस्लिम देशों में आज भी ४-६ बच्चे वाले परिवार बहुतायत में हैं | इसी लिए जहाँ भारतीय सेना में सैनिक अफसरों

के लिए लड़के नहीं मिलते , पाकिस्तान में सेना में जाने के लिए लड़को की क़तार लगी रहतीं हैं | इसी लिए आज शायद विश्व में मुस्लिम देशों में हिन्सक सधर्ष सबसे अधिक है |

भारत और अमेरिका, दोनो की, समस्या का समाधान उनके साझा समझौते में है | अमेरिका और नाटों देशों की वायुसेना और जलसेना , पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह स्तंभित करने में समर्थ है , और भारत जमीन पर नियंत्रण करने के लिए जरुरी सैनिक दे सकता है | समझौते का उदेश्य , अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जड़ से खात्मा और १९४६ -४७ में ब्रिटेन द्वारा किए गए भूलों का परिमार्जन होना चाहिए |

१९४६ तक भारत के विभाजन की कोई बात नहीं थी | इससे पहले , दूसरा विश्व युद्ध जब अपनी परिणिति की ओर बढ़ रहा था और सोवियत सेनाएँ जर्मनी में प्रवेश कर चुकी थीं , इंग्लैंड के प्रधान मंत्री श्री चर्चिल ने दिल्ली स्थित भारतीय उपमहाद्वीप एवं मध्य पूर्व के सामरिक सलाहकार जनरल आर . सी . मनी को युद्ध ख़त्म होने के बाद , सोवियत संध से भारत पर होने वाले खतरों के बारे में १५ दिनों में रिपोर्ट देने को कहा | जनरल मनी ने चर्चिल को अपनी रिपोर्ट में मध्यपूर्व , ईरान और उपमहाद्वीप पर सोवियत संध के प्रभाव को रोकने के लिए भारत के उतर- पच्छिम हिस्से में (बलोचिस्तान, सीमांत प्रांत) ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा सैनिक अड्डे बनाने की जरूरत बताई | भारत के तत्कालीन बाइसराय जनरल वावेल ने जब कांग्रेस के नेताओं , पंडित नेहरू और सरदार पटेल से इस बारे में राय जाननी चाही तो दोनों ने , स्वत्रंत भारत में किसी विदेशी सैनिक अड्डे की संभावना को पूरी तरह नकार दिया | वस्तुतः, इस समस्या से निबटने के लिए, कलात राज्य (बलोचिस्तान) को स्वतंत्र करने की योजना बनाई गई और ५ अगस्त १९४७ को भारत और पाकिस्तान की आजादी से १० दिन पहले , कलात को एक स्वतंत्र राष्ट्र धोषित कर दिया गया | जब भारत के विभाजन की बात उठी और श्री जिन्ना ने ब्रिटिश अमेरिकी सैन्य सहयोग की मंशा जताई , तब अंग्रेजो को लगा , कलात जैसे एक छोटे राज्य के बजाए पाकिस्तान से सैन्य सहयोग बेहतर होगा और उन्होंने भारत के विभाजन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया | यही नहीं , लन्दन के तत्कालीन भारत सचिव लार्ड लिस्तोवेले ने भारत के वाइसराय लार्ड माउन्टबेटेन को एक सन्देश भेजा की कलात को स्वतंत्र रखना बहुत जोखिम का हो सकता है अत: पाकिस्तान को ऐसा कुछ भी करने से रोका जाए , जो कलात को एक सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता हो | अंतत २० अप्रैल १९४८ को पाकिस्तानी सेनाओं ने अंग्रेज मेजर जनरल मैसी और ब्रिगेडियर अकबर खां के नेतृत्व में कलात पर हमला किया और रात २ बजे , कलात के शाशक नवाब रहीम यार खां द्वारा जबरन विलय के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए | बलोच तभी से अपनी आजादी को लिए संधर्ष कर रहे हैं |

इस पूरे कार्यक्रम को यदि कोई देश बिगाड सकता है तो वह है , चीन | चीन, अपने पश्चिमी इलाके, सिन्कीयांग, को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना चाहता है | यदि चीन को आश्वस्त कर दिया जाये कि उसके असैनिक व्यापार में बाधा नहीं डाली जाएगी और उसके इस रास्ते के उपयोग का आधिकार बना रहेगा, वह भी बहुत विरोध नहीं करेगा |

भाग्यवश, अमेरिका मे आज एक ऐसा प्रशासन है, जो बड़े खतरे लेने से नहीं हिचकिचाता | उन्हें अफगानिस्तान में आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा है | अत : वे पाकिस्तान को धमकाते भी है और फिर उसी के पास जाते भी हैं ताकि वह किसी तरह तालिबान को मेज पर लाए जिससे कि वे वहाँ से निकल सकें | हमें अमेरिका को समझाना चाहिए कि तालिबान समझौता नही चाहते | वे जमीन के लिए नहीं , विचारघारा के लिए लड़ रहे हैं | उनमे अलकायदा , आई एस , जमात - उद्दावा आदि में कोई फर्क नही है | उनका लक्ष्य अफ़गानिस्तान में नियंत्रण से खत्म नहीं होता , वह केवल पहला कदम है | उनका लक्ष्य पूरे विश्व में अमेरिका , यूरोप सहित, इस्लामिक शासन लाने से पूरा होता है | उसके लिए, वे यदि समझौता कर भी ले, तो वे उसे तोड़ेंगे | इसके लिए कितना भी संधर्ष करना पड़े, वे करेंगे | उनके लिए जिहाद में शहादत भी एक लक्ष्य है क्योंकि उसके द्वारा वह सीधे जन्नत जाते है, उन्हें क़यामत तक अल्लाह के बुलाने का इंतजार नहीं करना पड़ता | पाकिस्तानी सेना का भी लक्ष्य यही है | विश्वास नही है तो केवल पाकिस्तानी सेना का मोटो देख लें | पाकिस्तानी सेना का मोटो है , " जिहादे सबी अल्लाह "यानी अल्लाह के लिए जिहाद | दोनो एक दूसरे के पूरक है |

पाकिस्तान ने १९७१ में हमें एक मौका दिया था, १९४७ में अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई विसंगतियों को सुधारने का |तात्कालीन राजनैतिक नेतृत्व ने इसे आधा ही किया | सेना द्वारा खोले गए संभावनाओं का पूरा फायदा नहीं उठाया गया और जो थोड़ी बहुत बढ़त मिली भी थी , उसे शिमला समझौता में खो दिया गया | आज हमारे राजनैतिक नेतृत्व को एक बार फिर मौका मिला है , इतिहासिक भूलों को सुधारने का | हमारा लक्ष्य पूरे जम्मू कश्मीर की पाकिस्तानी अतिक्रमण से मुक्ति , बलोचिस्तान खैबर पख्तुनवा एवं सिंध मे जनमत संग्रह द्वारा उनके भविष्य का निर्णय , इस प्रकार पाकिस्तान का पुनर्गठन और पाकिस्तानी सेना की काट छांट होना चाहिए | पुनर्गठित पाकिस्तान की सीमाओं की गारंटी यदि अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन, रूस, ईरान समेत सभी देश दे दें तो उसका दायरा केवल आंतरिक शांति बनाये रखने का हो जाता है, उसी के अनुसार उसे पुनर्गठित करना चाहिए | सवाल यह है कि क्या आज के भारतीय नेतृत्व के पास इतना साहस और दूरदृष्टी है कि वह इस निर्णायक समझौते की पहल कर सके |

के . नाथ